पटना उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 1300

थाना कांड संख्या- वर्ष-0, थाना- जिला- खगड़िया से उद्भूत

==========

नथुनी पासवान पिता स्वर्गीय श्रीलाल पासवान निवासी- गाँव-लाभगाँव, थाना -गणगौर, जिला-खगड़िया

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. रेणु कुमारी पिता स्वर्गीय महेंद्र चौधरी निवासी- वर्तमान में क्वार्टर- सदर अस्पताल के पास, थाना-चित्रगुप्त नगर, खगड़िया, जिला-खगड़िया।

... ...प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राजेश सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता
		श्री चंदन कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री चंद्र सेन प्रसाद सिंह, अ.लो.अ
विपक्षी सं. 2 के लिए	:	श्री बिनोद कुमार, विद्वान अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125— भरण-पोषण — याचिकाकर्ता को अपोजिट पार्टियों (दूसरी पत्नी और बेटी) को भरण-पोषण राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया—याचिकाकर्ता ने दूसरी पत्नी के साथ अपनी शादी की अवैधता का दावा किया, जो या तो उसके या याचिकाकर्ता/पत्नी के विवाह के कारण है, उसे स्वयं या याचिकाकर्ता/पत्नी के पूर्व विवाह के आरोप को कड़े सबूतों के साथ साबित करने की आवश्यकता है—याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि अपोजिट पार्टी पहले से किसी और से विवाहित थी—दूसरी पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से यह साबित किया कि याचिकाकर्ता ने उसे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार मंदिर में विवाह किया, अपने पहले विवाह को उससे छिपाते हुए—अतः वह अपनी पहली पत्नी के साथ अपने पहले विवाह का दावा नहीं कर

सकता ताकि यह दिखा सके कि उसकी दूसरी पत्नी के साथ विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है—याचिकाकर्ता ने अपनी दूसरी पत्नी के पति को कार्यवाही में नहीं जोड़ा, क्योंकि वह आवश्यक पक्ष था और बिना उसकी उपस्थिति के कार्यवाही में, उसकी दूसरी पत्नी के साथ वैवाहिक स्थिति की घोषणा नहीं की जा सकती—दूसरी पत्नी (अपोजिट पार्टी) याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और बेटी उनके विवाह से जन्मी है और बेटी नाबालिग है—अतः दोनों कानून के अनुसार याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए योग्य हैं —दोनों अपोजिट पार्टियां याचिकाकर्ता के नाम पर आवंटित सरकारी क्वार्टर में रह रही हैं और याचिकाकर्ता की सैलरी से किराया काटा जा रहा है—याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत, आक्षेपित आदेश में संशोधन करते हुए।

(पैराग्राफ 55 से 60)

(1988) 1 एससीसी 530; (2005) 3 एससीसी 636; (2014) 1 एससीसी 188; (1991) 2 एससीसी 375; (1998) 8 एससीसी 447; (1999) 7 एससीसी 675; (2002) 10 एससीसी 510; (2011) 1 एससीसी 141; (2011) 12 एससीसी 189; (2019) 11 एससीसी 491; (2002) 5 एससीसी 422; 2003 एससीसी ऑनलाइन पटना 1083; (2021) 13 एससीसी 99; (2010) 10 एससीसी 469-- ***निर्भर किया गया ।***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

तिथि - 18-03-2025

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा 2014 के भरण पोषण मामला संख्या 32 एम में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 14.08.2019 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को विपक्षी संख्या 2/रेणु कुमारी और उनकी बेटी पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी को रु. 10,000/- और रु. 5, 000/- प्रत्येक को प्रतिमाह देने का आदेश दिया गया है।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि विपक्षी सं. 2/रेणु कुमारी ने स्वयं और अपनी ढाई साल की बेटी पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी के भरण पोषण के लिए 03.07.2014 को धारा 125 दं. प्र. सं. के तहत 2014 का भरण पोषण मामला नंबर 32 एम. दायर किया था। यह दावा करते हुए कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और उनकी बेटी पीहू कुमारी उर्फरुचि कुमारी का जन्म विवाह से हुआ है। उनके दावे के अनुसार, याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान के साथ उनकी शादी हिंदू रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार शिव मंदिर, देवघर में 25.06.2002 को हुई थी।

3. विपक्षी सं.2/रेणु कुमारी द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान ने गुलाबी देवी के साथ अपनी पहली शादी को छुपाया था और सरकारी नौकरी पाने में सहायता प्रदान करने के बहाने सदर अस्पताल, खगड़िया के सरकारी क्वार्टर में उसका यौन शोषण किया था। जब वह अपनी बेटी पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी की गर्भावस्था में जन्म दे रही थी, तो याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान ने शिव मंदिर, देवघर में उससे शादी कर ली। उसने आगे दावा किया है कि याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है और उसकी वार्षिक आय रु. 8,00,000 है।

4. यह भी आरोप लगाया गया है कि जब उसे याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान की पहली शादी के बारे में पता चला, तो याचिकाकर्ता ने उससे कहा कि उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है और वह उसके साथ रहेगा। इसके बाद, उसने रेणु कुमारी और उसकी बेटी पिहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी को सरकारी क्वार्टर, खगड़िया में छोड़ दिया। जब वह फिर से नथुनी पासवान से मिली, तो उसके साथ मारपीट की गई और उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, 494 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए महिला पुलिस थाना मामला संख्या 23/2013 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया, जो अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। भरण-पोषण की उसकी लगातार मांग के बावजूद, याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान द्वारा उसका भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है और वह खुद

अपना और अपनी बेटी पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि नथुनी पासवान ने अपनी बेटी के नाम पर एलआईसी पॉलिसी नंबर 529208601 भी खोली है।

5. नोटिस पर, याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और अपना कारण बताओ आवेदन दाखिल किया, जिसमें उन्होंने रेणु कुमारी द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी रेणु कुमारी से विवाह किया है और वे उनकी बेटी पिहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी के जैविक पिता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, जबकि रेणु कुमारी जाति से भूमिहार हैं और उनकी शादी पहले ही धीरज सिंह, ग्राम सदानंदपुर, पी.एस. बलिया, जिला- बेगूसराय के निवासी से हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रशिक्षित ए.एन.एम. हैं और वे खुद को नथुनी पासवान की पत्नी बताकर आरक्षण का लाभ उठाकर सरकारी नौकरी पाना चाहती थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शादी पहले ही गुलाबी देवी से हो चुकी है और उनके विवाह से उनका 32 वर्षीय बेटा और 36 वर्षीय बेटी है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनकी वार्षिक आय 8,00,000/- रुपये है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी पाने में सहयोग न करने के कारण उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि रेणु कुमारी एक प्रशिक्षित ए.एन.एम. हैं और एक निजी नर्सिंग होम में काम कर रही हैं, जहाँ उन्हें 10,000/- रुपये प्रति माह मिलते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें रेणु कुमारी की बेटी के नाम पर किसी भी एलआईसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है।

6. मुकदमे के दौरान, आवेदक रेणु कुमारी की ओर से निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की गई है।

(i) **रेणु कुमारी स्वयं अ.सा.-1** के रूप में।

(ii) **वीणा देवी अ.सा.-2** के रूप में, जो पिछले एक साल से खगड़िया के सदर अस्पताल में आशा दीदी के रूप में काम कर रही हैं और सदर अस्पताल, खगड़िया में नौकरानी के रूप में भी काम कर रही हैं।

(iii) **अंजुला देवी अ.सा.-3** के रूप में, जो सदर अस्पताल, खगड़िया में रेणु कुमारी के सरकारी क्वार्टर के पास एक चाय की दुकान चलाती हैं।

(iv) **पीहू कुमारी अ.सा.-4** के रूप में, जो रेणु कुमारी की बेटी हैं।

(v) **मिथलेश देवी अ.सा.-5** के रूप में, जो रेणु कुमारी की माँ हैं।

7. उसने मुकदमे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैंः

(i) **प्रदर्श -1**-रेणु कुमारी के नाम का मतदाता पहचान पत्र जिसमें नथुनी पासवान को उनके पति के रूप में दिखाया गया है और कार्ड 23.01.2016 पर जारी किया जा रहा है।

(ii) **प्रदर्श -2**-रेणु कुमारी के नाम का आधार कार्ड, जिसमें नथुनी पासवान को उनके पति के रूप में दिखाया गया है। हालाँकि, इसके चेहरे पर जारी करने की तारीख नहीं है।

(iii) **प्रदर्श -3**-भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 494 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नथुनी पासवान के खिलाफ 26.08.2013 पर दर्ज 2013 के खगड़िया महिला थाना केस नंबर 23 की फोटोकॉपी।

(iv) **प्रदर्श -4**-भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 494 और 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए नथुनी पासवान के खिलाफ 2013 की महिला थाना मामला संख्या 23 में दायर 2013 की संख्या 39 वाली आरोप-पत्र की फोटोकॉपी। दिनांक- 30.11.2013।

(v) **प्रदर्श -5**-2013 के जी. आर. सं. 1839 में विद्वान S.D.J.M, खगड़िया द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2018।

(vi) **प्रदर्श -6**-पटना उच्च न्यायालय द्वारा सीआर में पारित आदेश दिनांक 07.03.2014। विविध आपराधिक वाद। 2013 का सं. 47490, जिसके तहत नथुनी पासवान को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें रेणु कुमारी को उनके भरण-पोषण के लिए प्रति माह Rs.1200 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

रेणु कुमारी का साक्ष्य

(पारिवारिक न्यायालय के समक्ष आवेदक और यहां विपक्षी संख्या 2)

8. **रेणु कुमारी** (अ.सा.-1) के साक्ष्य पर आते हुए, जो पारिवारिक न्यायालय के समक्ष आवेदक थी, मैंने पाया कि उसने अपने मुख्य परीक्षण में अपने बयान को दोहराते हुए अपने आवेदन का समर्थन किया है। 24.01.2017 को आयोजित उसके **जिरह** में, उसने यह बयान दिया है कि वह पिछले 4 वर्षों से अपने पति से अलग रह रही है और उसकी बेटी 5 वर्ष की है। उसने यह भी दावा किया कि उसके पास उसकी बेटी के जन्मदिन की फोटो है और उसके पति के पास उसकी बेटी के नाम से खोली गई एलआईसी पॉलिसी का दस्तावेज भी है और उसकी बेटी का जन्म नर्सिंग होम में हुआ था, जिसका प्रमाण पत्र उसके पास है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसके पति के नाम पर एक सरकारी क्वार्टर आवंटित है और वह उसी क्वार्टर में रह रही है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसके आधार कार्ड पर भी उसके पति के रूप में नथुनी पासवान का नाम है। उसके बैंक खाते में भी उसके पति के रूप में नथुनी पासवान का नाम है। उसके पास राशन कार्ड भी है। उसने आगे यह भी बयान दिया है कि उसका पैतृक जिला बेगूसराय है और वह नौकरी की तलाश में वर्ष 2002 में खगड़िया गई थी। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और इस प्रमाण पत्र पर के एस के एस केएसजी/2011/सीएसटी/8602 दिनांक 19.07.2011 अंकित है। उसने आगे यह भी बयान दिया हैकि गुलाबी देवी, जो नथुनी पासवान की पत्नी है, ने उसके पति नथुनी पासवान के नाम का उपयोग करके जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। उसने यह भी बयान दिया है कि मंदिर में उसकी शादी से संबंधित सभी फोटो और रसीद नथुनी पासवान के पास है और इसीलिए वह ऐसे दस्तावेज न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकी। उसने आगे यह भी बयान दिया है कि वह नथुनी पासवान से पहली बार वर्ष 2002 में नौकरी की तलाश में खगड़िया अस्पताल में मिली थी। उसकी बेटी की जन्म तिथि 09.02.2012 है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नथुनी पासवान के

खिलाफ यौन शोषण के लिए कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया है, क्योंकि उन्होंने उनसे विवाह किया था। उनकी बेटी पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी के नाम पर एलआईसी पॉलिसी उनके पति नथुनी पासवान ने खरीदी थी, जो वर्तमान में बंद है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने नथुनी पासवान को अपना पति दिखाने के लिए अपनी बेटी के नाम पर एलआईसी पॉलिसी ली है। उन्हें आधार कार्ड जारी करवाने का वर्ष याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि वे जानबूझकर आधार कार्ड जारी करने की तारीख छिपा रही हैं, क्योंकि आधार कार्ड उन्होंने वर्तमान मामला दर्ज करने के बाद प्राप्त किया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनकी शादी धीरज सिंह पुत्र स्वर्गीय सरंधर सिंह, निवासी ग्राम-सदनपुर, जिला-बेगूसराय से पहले ही हो चुकी थी, जिसे वे छिपा रही हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि नथुनी पासवान उनकी बेटी के पिता नहीं हैं।

9 . अ.सा. -2 वीणा देवी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में रेणु कुमारी के मामले का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि रेणु देवी और नथुनी पासवान 10-11 वर्षों से एक साथ रह रहे हैं तथा उनकी शादी देवघर में हुई थी और वह सरकारी क्वार्टर में रह रही हैं, जो नथुनी पासवान को आवंटित है। अपने जिरह में उन्होंने यह भी बयान दिया है कि वह खगड़िया अस्पताल में आशा दीदी के रूप में पिछले एक वर्ष से काम कर रही हैं तथा इससे पहले वह सदर अस्पताल में करीब 15 वर्षों तक सेविका के रूप में काम कर चुकी हैं। वह रेणु देवी को वर्ष 2002 से जानती हैं। उन्होंने सुना था कि रेणु देवी और नथुनी पासवान ने वर्ष 2002 में शादी कर ली थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि रेणु देवी की शादी धीरज सिंह के साथ वर्ष 2002 में हुई थी, जिसे वह छिपा रही हैं।

10. अ.सा. -3 अंजुला देवी है। वह रेणु देवी के सरकारी क्वार्टर के पास चाय की दुकान चलाती है। उसने भी अपने मुख्य परीक्षण में रेणु देवी के मामले का समर्थन किया है। अपने जिरह में उसने यह बयान दिया है कि वह पिछले 5 वर्षों से रेणु देवी से

परिचित है। उसने इस बात से इनकार किया है कि रेणु देवी की शादी बेगूसराय के धीरज सिंह से हुई थी और वह एक निजी नर्सिंग होम में काम करती है और 10 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमाती है।

11. अ.सा. -4 रेणु कुमारी की ***7* वर्षीय पुत्री पीहू कुमारी** है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने यह बयान दिया है कि उसके माता और पिता साथ नहीं रहते हैं और उसके पिता उसकी मां को खाना, कपड़ा आदि नहीं देते हैं, हालांकि वह उसे ये चीजें मुहैया कराते हैं और उसकी मां सिर्फ घरेलू काम करती है और वह पैराडाइज स्कूल, खगड़िया में पढ़ती है। वह नहीं जानती कि उसका दाखिला स्कूल में किसने कराया था, लेकिन उसके पिता उसके साथ उसके स्कूल गए थे। जिरह में उसने यह बयान दिया है कि एक चाचा उसके घर आते हैं, लेकिन वह उनका नाम नहीं जानती। उसकी मां उसे स्कूल में छोड़ जाती है। फीस उसके पिता जमा करते हैं। उसने इस बात से इनकार किया है कि नथुनी पासवान उसके पिता नहीं हैं और वे उसकी फीस जमा नहीं करते। उसने यह भी बयान दिया है कि नथुनी पासवान कभी उसके घर नहीं आते। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसकी मां उसे पढ़ाती है।

12. अ.सा. -5 मिथलेश देवी जो रेणु कुमारी की मां हैं। अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने अपनी बेटी रेणु कुमारी के मामले का भी समर्थन किया है। जिरह में उसने यह बयान दिया है कि वह नथुनी पासवान के घर कभी नहीं गई और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य से मिली। वह भूमिहार जाति से है। वह धीरज सिंह पुत्र सारंधर सिंह को नहीं जानती। उसने इस बात से इनकार किया है कि रेणु कुमारी की उससे शादी हुई थी।

13. याचिकाकर्ता ने अपने कारण बताए जाने के समर्थन में निम्नलिखित गवाहों से भी पूछताछ की हैः-

(i) हरेराम सिंह विपक्षी सा सं -1 के रूप में, जो धीरज सिंह के सह-ग्रामीण हैं।

(ii) अशोक यादव को विपक्षी सा सं -2 के रूप में, जो नथुनी पासवान के सह-ग्रामीण हैं।

(iii) संजय कुमार को विपक्षी सा सं -3 के रूप में, जो नथुनी पासवान के पुत्र हैं।

(iv) नथुनी पासवान स्वयं विपक्षी सा सं -4 के रूप में।

नथुनी पासवान के साक्ष्य

(पारिवारिक न्यायालय के समक्ष विरोधी पक्ष और यहाँ याचिकाकर्ता)

14. नथुनी पासवान ने खुद को विपक्षी सा सं 4 के रूप में बयान दिया है। अपने मुख्य परीक्षण में, उन्होंने कहा है कि वर्ष 1974 में उनकी शादी गुलाबी देवी से हुई थी और उनकी 36 साल की बेटी और 32 साल का पुत्र है, जो शादी में बाहर है और उनकी पत्नी गुलाबी देवी उनके साथ रह रही है। वह रेणु देवी को पिछले 12-13 वर्षों से जानते हैं। वह एक जय प्रकाश के माध्यम से सदर अस्पताल, खगड़िया में उससे परिचित हुआ। रेणु देवी सदर अस्पताल में निजी नर्स के रूप में काम कर रही थीं। यह कहना गलत है कि उन्होंने रेणु देवी से शादी की और वे उनकी बेटी के पिता हैं। वह लगभग 20 वर्षों से हृदय रोगी हैं। अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि उनका मासिक वेतन Rs.70,000/- है और खगड़िया में उन्हें कोई सरकारी क्वाटर आवंटित नहीं की गई है। जब 6 साल की पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी को दिखाया गया, तो उसने इनकार कर दिया कि वह उसकी बेटी है। उसने यह भी बयान दिया है कि उसके पास कोई भूमि संपत्ति नहीं है। खगड़िया जिले के लाभगांव में उनका केवल एक आवासीय घर है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या रेणु देवी का नाम उनके परिवार के सदस्य के रूप में सूचीबद्ध है और उनके नाम पर आधार कार्ड जारी किया गया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनकी पत्नी गुलाबी देवी ने सिविल सर्जन, खगड़िया से इस आशय की शिकायत की है कि उन्होंने रेणु देवी के साथ दूसरी शादी कर ली है और वह उन्हें अपने सरकारी आवास में रख रहे हैं। उन्होंने इस सुझाव का भी खंडन किया है कि उनके कहने पर, नर्सिंग होम ने उन्हें पिता के

रूप में दर्शाते हुए रेणु देवी की बेटी के जन्म के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया था। जब उनका सामना रेणु देवी के साथ एक तस्वीर के साथ किया गया, तो उन्होंने उस तस्वीर को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने रेणु देवी के नाम पर एल. आई. सी. पॉलिसी जारी कराई है और उन्होंने कुछ किश्तों का भुगतान भी किया है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने खगड़िया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को सूचित किया था कि उन्होंने सरकारी क्वार्टर खाली कर दिया था जो उन्हें आवंटित किया गया था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि खगड़िया के जिला मजिस्ट्रेट ने एक लिखित आदेश जारी किया था कि रेणु कुमारी उनके द्वारा खाली किए गए सरकारी क्वार्टर में रहेंगी और मासिक किराया उनके वेतन से काट लिया जाएगा। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने सरकारी क्वार्टर के पास स्थित पैराडाइज स्कूल में पीहू कुमारी को भर्ती कराया था और उनका नाम उनके पिता के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, उन्होंने बयान दिया है कि अगर पीहू कुमारी के पितृत्व का परीक्षण करने के लिए डीएनए परीक्षण किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

15. **विपक्षी सा सं -1 हरेराम सिंह** हैं। वे बेगूसराय जिले के सदानंदपुर के निवासी हैं तथा धीरज सिंह पुत्र सारंधर सिंह के सगे भाई हैं। अपनी जांच तिथि 29.05.2019 को उन्होंने यह बयान दिया है कि लगभग 20 वर्ष पूर्व धीरज सिंह ने रेणु देवी पुत्री महेंद्र चौधरी, निवासी डीहा से विवाह किया था तथा विवाह के पश्चात रेणु देवी उनके ससुराल सदानंदपुर में आकर 3 से 4 वर्ष तक रही तथा उसके पश्चात वह अपने ससुराल से जय प्रकाश उर्फ जे.पी. के साथ चली गई तथा उसके पश्चात वह कभी वापस धीरज सिंह के पास नहीं आई, जो अभी भी अपने घर पर रह रहा है तथा उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिरह में उन्होंने यह बयान दिया है कि धीरज सिंह के साथ रेणु देवी की शादी में उनके भाई सियाराम भी शामिल हुए थे, लेकिन वे शादी के समय रेणु देवी की सही उम्र नहीं बता पाए। उन्हें नहीं पता कि रेणु देवी और नथुनी पासवान के बीच वैवाहिक संबंध है या नहीं। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्हें नहीं पता कि नथुनी पासवान ने

रेणु देवी को नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण किया या नहीं और उसके बाद नथुनी पासवान ने रेणु देवी से शादी कर ली और उसे अपने सरकारी क्वार्टर में रखने लगा।

16. विपक्षी सा सं 2-अशोक यादव है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि वह रेणु देवी से परिचित है। वर्ष 2016 में जब उसकी पुत्री गर्भवती थी और उसे प्रसव के लिए सदर अस्पताल, खगड़िया में भर्ती कराया गया था, तब वह जय प्रकाश नामक व्यक्ति के पूछने पर सदर अस्पताल, खगड़िया गया था। जय प्रकाश ने उसे रेणु कुमारी के बारे में बताया था जो गौशाला रोड स्थित मीनू नर्सिंग होम में ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत थी। उस दौरान रेणु कुमारी ने उससे कुछ पैसे मांगे थे और कहा था कि वह नर्सिंग होम से मात्र 8 से 10 हजार रुपये कमाती है। उसने यह भी बताया था कि उसका ससुराल बेगूसराय जिले के सदानंदपुर में है। वह नथुनी पासवान से भी परिचित है, क्योंकि वह उसका सह-ग्रामीण है। उसकी पत्नी का नाम गुलाबी देवी है और उसका एक पुत्र और एक पुत्री भी है। जिरह के दौरान उन्होंने यह बयान दिया कि नथुनी पासवान स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनके वेतन की सही राशि के बारे में पता नहीं है। नथुनी पासवान सरकारी क्वार्टर में नहीं बल्कि अपने घर में रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि नथुनी पासवान के पास कोई ज़मीन-जायदाद है या नहीं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि नथुनी पासवान के दोस्त होने के कारण उन्होंने झूठी गवाही दी है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि नथुनी पासवान और रेणु कुमारी के बीच विवाह संपन्न कराने में उनकी सक्रिय भूमिका थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि रेणु कुमारी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

17. विपक्षी सा सं -3 संजय कुमार पिता नथुनी पासवान है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने यह बयान दिया है कि उसकी मां का नाम गुलाबी देवी है और उसकी शादी उसके पिता के साथ वर्ष 1974 में हुई थी। वह रेणु देवी को भूमिहार जाति से होने के कारण जानता है, लेकिन उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए खुद को अनुसूचित जाति का

बताते हुए जाति प्रमाण पत्र बनवाया है और उसके पिता को पति के रूप में दर्शाया है। जब उसकी मां को उसके प्रमाण पत्र के बारे में पता चला तो उसकी मां ने चित्रगुप्त थाना, खगड़िया में रेणु कुमारी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उसने यह भी बयान दिया है कि उसकी मां ने उसके पिता नथुनी पासवान के खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। अपने जिरह में उसने उस लड़की के बारे में भी अनभिज्ञता जताई है, जिसे उसकी बेटी बताया जा रहा है। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने और उसकी मां ने स्थानीय मुखिया के समक्ष अपने पिता की रेणु देवी के साथ दूसरी शादी के संबंध में कोई संयुक्त आवेदन दिया है। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया है कि उन्होंने और उनकी मां ने सिविल सर्जन, खगड़िया को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि उनके पिता ने रेणु देवी से दूसरी शादी कर ली थी। वे रेणु देवी के मायके या ससुराल नहीं गए हैं। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया है कि जब रेणु देवी ए.एन.एम. के पद पर नौकरी करने जा रही थीं, तब उनके पिता ने इस आशय का एक आवेदन दिया था कि रेणु देवी ने अपने पहले पति के जीवनकाल में ही उनसे शादी कर ली है।

परिवार न्यायालय के निष्कर्ष और आदेश

18. अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री के अनुसार, विद्वान परिवार न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नथुनी पासवान ने गुलाबी देवी के साथ अपनी पहली शादी को छिपाते हुए रेणु कुमारी से शादी की थी और रेणु देवी और नाथू पासवान के बीच विवाह के कारण, उनकी एक संतान, पीहू कुमारी का जन्म हुआ था। विद्वान परिवार न्यायालय ने यह भी पाया है कि रेणु कुमारी के पास अपना और अपनी नाबालिग बेटी का भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं है, जबकि नथुनी पासवान का मासिक वेतन रु। 70, 000 है। इसलिए, विद्वान परिवार न्यायालय ने नथुनी पासवान को भुगतान करने का निर्देश दिया। 10,000/- प्रति माह रेणु कुमारी को और रु. 5, 000/- प्रति माह पीहू कुमारी को उनके भरण पोषण के लिए। आवेदन दाखिल करने यानी दिनांक 03.07.2014 से जब तक रेणु देवी की पुनर्विवाह नहीं हो जाती और पीहू कुमारी की शादी नहीं हो जाती।

पक्षों की दलीलें

19. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना, राज्य के लिए सहायक लोक अभियोजक को सुना और विपक्षी सं. 2 के लिए विद्वान वकील को सुना।

नथुनी पासवान की ओर से निवेदन

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि आक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान ने कभी भी रेणु कुमारी से शादी नहीं की है, और न ही वह रेणु कुमारी की बेटी पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी के जैविक पिता हैं।

21. वह यह भी प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता सरकारी सेवा में है और अनुसूचित जाति समुदाय से है। वह खगड़िया के एक सरकारी सदर अस्पताल में लिपिक था और रेणु कुमारी एक प्रशिक्षित ए. एन. एम है और वह उस अस्पताल में नौकरी की तलाश में थी। उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए उसकी मदद मांगी। उसने याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उससे भरण-पोषण प्राप्त करने का मनगढ़ंत आरोप लगाया है।

22. वह आगे निवेदन करता है कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता और विपक्षी सं.2 के बीच कभी शादी हुई थी। लेकिन अभिलेख पर बिना किसी सबूत के। विद्वान परिवार न्यायालय ने गलती से अभिनिर्धारित किया है कि विपक्षी संख्या 2/रेणु कुमारी याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है और पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी उनकी बेटी है और उनके पक्ष में भरण-पोषण प्रदान किया है।

23. वह आगे प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा था और उसके दो बड़े बच्चे हैं। रेणु कुमारी की भी पहले से ही एक धीरज सिंह के साथ शादी हो

चुकी है और इसलिए नथुनी के साथ उनकी कथित शादी उनकी जानकारी में द्विविवाह के कारण वैध शादी नहीं है।

24. इसलिए, नथुनी पासवान की ओर से यह निवेदन किया जाता है कि रेणु कुमारी और उनकी बेटी, पीहू कुमारी के भरण पोषण के लिए उसका कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

25. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि रेणु कुमारी और उनकी बेटी को दिए गए भरण-पोषण की राशि उनकी आय और उनके आश्रितों की संख्या को देखते हुए अधिक है।

<u>राज्य और रेणु कुमारी की ओर से निवेदन</u>

26. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान वकील और राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने आक्षेपित आदेश का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि रेणु कुमारी याचिकाकर्ता/ नथुनी पासवान की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थीं और पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी उनकी बेटी हैं।

27. अपनी दलीलों को साबित करने के लिए, वे आगे कहते हैं कि रेणु कुमारी सहित सभी गवाहों ने लगातार बयान दिया है कि शादी शिव मंदिर, देवघर में हुई थी। रेणु कुमारी की माँ ने यह भी बयान दिया है कि शादी के बाद, वह सदर अस्पताल, खगड़िया के सरकारी क्वार्टर में अपने पति/नथुनी पासवान के साथ रहने लगी। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित पूर्ववर्ती जमानत आदेश दिनांक 07.03.2024 में। विविध आपराधिक मामला वर्ष 2023 का है सं. 47490, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह रेणु कुमारी को पूरी गरिमा के साथ रखे और भरण पोषण के लिए रु। 1200/- प्रतिमाह जब तक कि उच्च

न्यायालय द्वारा कोई उच्च भरण पोषण नहीं दिया जाता है। वे आगे बताते हैं कि वोटर आईडी कार्ड 23.01.2016 को जारी किया गया है और उस कार्ड के अनुसार, नथुनी पासवान को रेणु कुमारी के पति के रूप में दिखाया गया है। रेणु कुमारी के नाम से आधार कार्ड भी जारी किया गया है। आधार कार्ड के अनुसार, नथुनी पासवान उनके पति हैं। वह अ.सा. -4 पीहू कुमारी उर्फरुचि कुमारी के बयान का उल्लेख करते हैं जिसमें उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि नथुनी पासवान उनके पिता नहीं हैं और यह भी कहा कि उसकी स्कूल की फीस पापा द्वारा जमा की जाती है।

वैधानिक प्रावधान और न्यायिक मिसालें

28. पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, धारा 125 सीआरपीसी का संदर्भ लेना उचित होगा जो पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित है। यह इस प्रकार है:

> "125. **पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश**। -
>
> (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, वह -
>
> (क) अपनी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
>
> (ख) अपनी वैध या नाजायज नाबालिग संतान, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
>
> (ग) अपनी वैध या नाजायज संतान (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जो वयस्क हो गई है, जहाँ ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या
>
> (घ) अपने पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, का भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण-पोषण करने से इनकार करता है,
>
> तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा या इनकार के सबूत पर ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता दे, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, और उसे ऐसे व्यक्ति को दे जैसा मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे: बशर्ते कि मजिस्ट्रेट नाबालिग बालिका के पिता को आदेश दे सकता है कि वह नाबालिग बालिका के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता दे।
>
> खंड (ख) में निर्दिष्ट, यदि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो कि ऐसी अवयस्क बालिका का पति, यदि विवाहित है, पर्याप्त साधन संपन्न नहीं है, तो उसे वयस्क होने तक ऐसा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है।

परंतु यह भी कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता दे और ऐसी कार्यवाही के व्यय, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और उसे ऐसे व्यक्ति को दे, जैसा मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे:

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्यवाही के व्यय के लिए आवेदन का, जहां तक संभव हो, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण। - इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन वयस्क नहीं माना जाता है,

(ख) "पत्नी" में ऐसी महिला सम्मिलित है, जिसका उसके पति द्वारा तलाक हो चुका है या उसने अपने पति से तलाक प्राप्त कर लिया है तथा उसने पुनः विवाह नहीं किया है।

(2) भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए ऐसा कोई भत्ता, आदेश की तिथि से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए आवेदन की तिथि से, जैसा भी मामला हो, देय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस प्रकार आदेश दिया गया है, बिना पर्याप्त कारण के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, जुर्माना लगाने के लिए प्रदान की गई विधि से देय राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, तथा ऐसे व्यक्ति को, वारंट के निष्पादन के पश्चात, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए प्रत्येक माह के भत्ते के पूरे या किसी भाग के लिए, जो भुगतान नहीं किया गया है, एक महीने तक की अवधि के लिए या यदि पहले भुगतान कर दिया गया है, तो कारावास की सजा दे सकता है:

बशर्ते कि इस धारा के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उस राशि को देय होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायालय में वसूलने के लिए आवेदन न किया जाए:

आगे यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर भरण-पोषण देने की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इंकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए इनकार के किसी भी आधार पर विचार कर सकता है, और इस धारा के तहत आदेश दे सकता है। ऐसी पेशकश के बावजूद, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए न्यायोचित आधार है।

स्पष्टीकरण - यदि पति ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है या रखैल रखता है, तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इंकार करने का न्यायोचित आधार माना जाएगा।

(4) कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि बिना किसी पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।

(5) यह साबित होने पर कि कोई पत्नी, जिसके पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया गया है, व्यभिचार में रह रही है, या कि बिना पर्याप्त कारण के वह अपने पति के साथ रहने से इंकार करती है, या कि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर देगा।

(जोर दिया गया)

29. इस प्रकार, धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार है, लेकिन **यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव एवं अन्य केस** (ऊपर) और **सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य केस** (ऊपर) के अनुसार, पत्नी का अर्थ है "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी"।

30. यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव और अन्य मामला (ऊपर), माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"4. फिर सवाल यह उठता है कि क्या संहिता की धारा 125 में उपयोग की गई "पत्नी"अभिव्यक्ति की व्याख्या केवल एक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में की जानी चाहिए जो अधिनियम की धारा 11 के दायरे में नहीं आती है। इस शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि स्पष्टीकरण में इसके समावेशी चरित्र का संकेत दिया गया है ताकि तलाकशुदा को शामिल किया जा सके। एक महिला तब तक तलाकशुदा नहीं हो सकती जब तक कि उस स्थिति से पहले कानून की नजर में कोई विवाह न हो। इसलिए, अभिव्यक्ति को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें यह स्पष्टीकरण (बी) के अधीन पक्षकारों के लिए लागू कानून में समझा जाता है, जो वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

.....

8.इसलिए, हम मानते हैं कि हिंदू संस्कारों के अनुसार एक महिला का विवाह एक जीवित पति या पत्नी वाले पुरुष के साथ करना कानून की नजर में पूरी तरह से अमान्य है और वह संहिता की धारा 125 के लाभ का हकदार नहीं है।

(जोर दिया गया)

31. सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य में मामला (ऊपर), माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

> "15. यमुनाबाई मामले [(1988) 1 एस. सी. सी. 530 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त "पत्नी"अभिव्यक्ति की व्याख्या केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में की जानी चाहिए। संहिता में "पत्नी"शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि धारा 125 के स्पष्टीकरण में इसके समावेशी चरित्र का संकेत दिया गया है ताकि तलाकशुदा को शामिल किया जा सके। एक महिला तब तक तलाकशुदा नहीं हो सकती जब तक कि उस स्थिति से पहले कानून की नजर में कोई विवाह न हो। इसलिए अभिव्यक्ति को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें इसे पक्षों के लिए लागू कानून में समझा जाता है। एक जीवित पति या पत्नी वाले पुरुष के साथ हिंदू संस्कारों के अनुसार एक महिला का विवाह कानून की नजर में पूरी तरह से अमान्य है और इसलिए वह संहिता की धारा 125 या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "विवाह अधिनियम") के लाभ का हकदार नहीं है। जीवित पति या पत्नी वाले व्यक्ति के साथ विवाह शून्य और अमान्य है और शून्यकरणीय नहीं है।
>
> .....
>
> **18.** इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि विधायिका ने प्रावधान के दायरे में एक अवैध बच्चे को शामिल करना आवश्यक समझा, लेकिन उसने कानूनी रूप से विवाहित महिला के संबंध में ऐसा नहीं किया है। हालाँकि यह वांछनीय हो सकता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दुर्भाग्यपूर्ण महिला की दुर्दशा पर ध्यान देने के लिए तर्क दिया है, विधायी इरादे संहिता की धारा 125 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने के कारण, "पत्नी"अभिव्यक्ति में कानूनी रूप से विवाहित महिला को शामिल करने के लिए कोई कृत्रिम परिभाषा पेश करके इसके दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
>
> (जोर दिया गया)

32. बादशाह बनाम सौ. उर्मिला बादशाह गोडसे और अन्न., (2014) 1 एस. सी. सी. 188, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान अपनी पहली जीवित शादी को छिपाकर किसी अन्य महिला से पुनर्विवाह करता है, तो दूसरी पत्नी भरण-पोषण का हकदार है। आदमी को अपनी गलती का फायदा उठाने और द्विविवाह की याचिका उठाने की अनुमति नहीं दी जा

सकती है। यमुनाबाई और सविताबेन मामले (उपरोक्त) ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा जिसका उल्लेख इस प्रकार हैः

> " 13.2.....जब उत्तरवादी 1 और याचिकाकर्ता के बीच विवाह संपन्न हुआ, तो याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी 1 को अपनी पहली शादी के बारे में अंधेरे में रखा था। प्रत्यर्थी 1 को एक गलत अभ्यावेदन दिया गया था कि वह एकल था और प्रत्यर्थी 1 के साथ वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम था। ऐसी परिस्थितियों में, क्या याचिकाकर्ता को अपनी गलती का लाभ उठाने और यह कहने की अनुमति दी जा सकती है कि उत्तरवादी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत याचिका दायर करके भरण-पोषण के हकदार नहीं हैं क्योंकि उत्तरवादी 1 याचिकाकर्ता की "कानूनी रूप से विवाहित पत्नी"नहीं है?हमारा जवाब नकारात्मक है। हमारा विचार है कि कम से कम धारा 125 सी. आर. पी. सी. के उद्देश्य के लिए, उत्तरवादी 1 को याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में माना जाएगा, जो ऊपर दिए गए दो निर्णयों की भावना के अनुसार होगा। इस कारण से, हमारी राय है कि यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव, (1988) 1 एस. सी. सी. 530 और सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य, (2005) 3 एस. सी. सी. 636 मामलों में इस न्यायालय के निर्णय केवल उन परिस्थितियों में लागू होंगे जहां एक महिला ने पहले जीवित विवाह की पूरी जानकारी रखने वाले पुरुष से शादी की हो। ऐसे मामलों में, उसे पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरी शादी की अनुमति नहीं है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रतिबंध है और इसलिए उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उक्त निर्णय उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां एक पुरुष उस महिला को पहले जीवित विवाह के बारे में अंधेरे में रखकर दूसरी बार शादी करता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे निर्णयों के दो समूहों का मिलान और सामंजस्य किया जा सकता है। .
>
> (जोर दिया गया)

33. विमला (के.) बनाम वीरास्वामी (के.), (1991) 2 एस. सी. सी. 375 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि -पति यह दलील दे रहा है कि याचिकाकर्ता महिला के साथ उसकी शादी उसकी पिछली जीवित शादी के कारण अमान्य है, उसे अपनी पिछली शादी का सख्त सबूत देकर अपनी पिछली शादी को साबित करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार हैः

> "3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य भटकाव और अभाव को रोकना है। भटकाव और अभाव। यह परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय की आपूर्ति के

> लिए एक त्वरित उपाय प्रदान करता है। जब पति द्वारा उपेक्षित पत्नी के इस दावे को नकारने का प्रयास किया जाता है कि उसे एक रखैल के रूप में चित्रित किया गया है, इस विशिष्ट दलील पर कि वह पहले से ही शादीशुदा था, तो अदालत पहले की शादी के सख्त सबूत पर जोर देगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में 'पत्नी'शब्द में एक ऐसी महिला शामिल है जिसका पति द्वारा तलाक हो गया है या जिसने अपने पति से तलाक ले लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया है। इस प्रकार पत्नी का कानूनी दर्जा न रखने वाली महिला को उद्देश्य के अनुरूप 'पत्नी'शब्द की समावेशी परिभाषा के भीतर लाया जाता है। हालाँकि, कानून के तहत एक दूसरी पत्नी जिसकी शादी पहली शादी के जीवित रहने के कारण अमान्य है, वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और इसलिए, इस प्रावधान के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है। इसलिए, वह कानून जो दूसरी पत्नी को धारा 125, सी. आर. पी. सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने से वंचित करता है, केवल इस कारण से कि विवाह समारोह हालांकि प्रथागत रूप से किया जाता है, कानूनी पवित्रता का अभाव है, केवल तभी लागू किया जा सकता है जब पति संतोषजनक रूप से कानूनी और वैध विवाह के निर्वाह को साबित करता है, विशेष रूप से जब संहिता में प्रावधान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से सामाजिक न्याय का एक उपाय है। हम यह पता लगाने में असमर्थ हैं कि उत्तरवादी ने मुद्दे में तथ्य का सख्त सबूत देकर भारी बोझ उठाया है। उच्च न्यायालय आवश्यक सबूत के मानक पर विचार करने में विफल रहा और अपीलार्थी के खिलाफ प्रश्न का निर्धारण करने में किसी भी सबूत पर आगे नहीं बढ़ा। इसलिए हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी भरण-पोषण का हकदार नहीं है। .
>
> (जोर दिया गया)

34. संतोष बनाम नरेश पाल, (1998) 8 एस. सी. सी. 447 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को पक्षकार की वैवाहिक स्थिति के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए आदेश पारित करने की आवश्यकता है और वैवाहिक स्थिति के संबंध में ऐसा निर्णय किसी भी दीवानी कार्यवाही में अंतिम आदेश के अधीन अस्थायी निष्कर्ष है, और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट और पटना उच्च न्यायालय के दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश को बहाल कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों के बीच कानूनी विवाह पाया था जिसमें कहा गया था कि उत्तरवादी , नरेश पाल ने पहले ही अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था और उसके बाद, उसने अपीलार्थी, श्रीमती संतोष के साथ दूसरी शादी कर ली

थी। संतोष, जो तलाकशुदा भी था, लेकिन उच्च न्यायालय ने एक विपरीत विचार रखते हुए कहा था कि पक्षों के बीच विवाह वैध नहीं था क्योंकि उत्तरवादी की पहली शादी, श्रीमती. संतोष का अपने पहले पति सत्येंद्र से तलाक नहीं हुआ था। माननीय उच्चतम न्यायालय के अवलोकन का उल्लेख किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः

> "2. .....धारा 125 सी. आर. पी. सी. (दंड प्रकिया संहिता) के तहत भरण पोषण के लिए एक कार्यवाही में विद्वान मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती थी कि वह पक्षों की वैवाहिक स्थिति के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद उचित आदेश पारित करे। यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय किसी भी दीवानी कार्यवाही में अंतिम आदेश के अधीन एक अस्थायी निर्णय होगा, यदि पक्षों को इसे अपनाने की सलाह दी जाती है। नतीजतन, हमारे विचार में उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक कार्यवाही में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त तथ्य के शुद्ध निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था और इसलिए केवल इस छोटे से आधार पर और पक्षकारों के वैवाहिक अधिकारों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जिन्हें दीवानी कार्यवाही में निर्णय लेना पड़ सकता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पारित विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि करनी होगी और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार करना होगा। अपील की अनुमति है। कोई लागत नहीं। "
>
> (जोर दिया गया)

35. द्वारका प्रसाद सत्पथी बनाम विद्युत प्रव दीक्षित, (1999) 7 एस. सी. सी. 675 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 125 दं. प्र. सं. के तहत एक कार्यवाही में विवाह के संबंध में सबूत का बोझ उतना सख्त नहीं है जितना कि एक मुकदमे में आवश्यक है। आई. पी. सी. (भारतीय दंड संहिता) की धारा 494 के तहत द्विविवाह का अपराध के मुकदमें के लिए आवश्यक है। यहाँ, यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 125 दं. प्र. सं. के तहत पारित आदेश अंततः पक्षों के अधिकारों का निर्धारण नहीं करता है और ऐसा आदेश दीवानी न्यायालय के आदेश के अधीन है। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "9. यह याद रखना चाहिए कि धारा 125 सी. आर. पी. सी. के तहत एक आवेदन में पारित आदेश अंततः पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित नहीं करता है और उक्त धारा को पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए एक संक्षिप्त उपाय प्रदान

करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया है। अपने अधिकारों को निर्धारित करने के उद्देश्य से, अपीलार्थी ने एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया है, जो निचली अदालत के समक्ष लंबित है। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय एस. सेतुरथिनम पिल्लई बनाम बारबरा [(1971) 3 एस. सी. सी. 923:1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 171] ने कहा कि धारा 488 सी. आर. पी. सी. 1898 (धारा 125 सी. आर. पी. सी. के समान) के तहत भरण पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है, जहां कुछ सबूत थे जिन पर भरण पोषण के अनुदान के लिए निष्कर्ष निकाला जा सकता था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 488 के तहत पारित आदेश एक संक्षिप्त आदेश है जो अंततः पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित नहीं करता है; आपराधिक अदालत का निर्णय कि पक्षों के बीच एक वैध विवाह था, पक्षों के बीच किसी भी दीवानी कार्यवाही में निर्णायक के रूप में काम नहीं करेगा।

10. बच्चे के पितृत्व पर विवाद नहीं करने के बाद और इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद कि विवाह समारोह किया गया था, हालांकि कानूनी रूप से सही नहीं है जैसा कि तर्क दिया गया है, अपीलार्थी के मुंह में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाही में यह तर्क देना मुश्किल होगा कि कोई वैध विवाह नहीं था क्योंकि उक्त विवाह के समय आवश्यक संस्कार नहीं किए गए थे। धारा 125 के तहत प्रावधान का उपयोग सामाजिक वातावरण की शिकार बेसहारा महिलाओं, बच्चों या माता-पिता को विधायिका द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को विफल करने के लिए नहीं किया जाना है। .

(जोर दिया गया)

36. प्रवती रानी साहू बनाम बिष्णुपद साहू, (2002) 10 एस. सी. सी. 510 मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कि उच्च न्यायालय को सकारात्मक हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए। विवाह और बच्चे के पितृत्व के पक्ष में निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

"5. ..... धारा 125 सी. आर. पी. सी. का उद्देश्य निर्धनता को कम करना और अनाथावस्था में सुधार करना है। उच्च न्यायालयों को विवाह और बच्चे के पितृत्व के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में देरी करनी चाहिए। अतः ऐसे मामलों में इस न्यायालय ने इंगित किया है कि उच्च न्यायालय ऐसे तथ्य निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उस सिद्धांत को वर्तमान मामले में आयात नहीं किया जा सकता है जहां मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप एक बच्चे को अपमानित किया गया था और दावेदार को वास्तव में अनैतिक नैतिकता वाली महिला पाया गया था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय

को पुनरीक्षण करना चाहिए था और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त निष्कर्ष या निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ हैं या नहीं। अपील और पुनरीक्षण के बीच समग्र दृष्टिकोण में अंतर बनाए रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. पुनरीक्षण के लिए आवेदन को संक्षिप्त रूप से खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का उपयोग भी नहीं किया गया है। इसलिए आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, हम आदेश को दरकिनार कर देते हैं और कानून के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिए पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय को वापस भेज देते हैं। "

(जोर दिया गया)

37. चानमुनिया बनाम विरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, (2011) 1 एस. सी. सी. 141 मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय यह विचार कि धारा 125 दं. प्र. सं. के तहत "पत्नी"को उन मामलों को भी शामिल करने के लिए व्यापक और विस्तृत व्याख्या दी जानी चाहिए जहां एक पुरुष और एक महिला उचित रूप से लंबे समय से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, और विवाह का सख्त प्रमाण धारा 125 दं. प्र. सं. के तहत भरण-पोषण के लिए एक पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए।

42. हमारी राय है कि व्यापक रूप से "पत्नी"शब्द की विस्तृत व्याख्या में उन मामलों को भी शामिल करने के लिए की जानी चाहिए जहां एक पुरुष और महिला उचित रूप से लंबे समय से पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, और विवाह का सख्त प्रमाण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए एक पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए, ताकि धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लाभकारी प्रावधान की सच्ची भावना और सार को पूरा किया जा सके। हम यह भी मानते हैं कि इस तरह की व्याख्या हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों, अर्थात् सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए उचित अनुप्रयोग होगी।

(जोर दिया गया)

38. पिला मुत्यालम्मा बनाम पिला सूरी देमुडू, (2011) 12 एस. सी. सी. 189 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कानून वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीने पर गुस्सा करता है। यह भी देखा गया है कि कानून विवाह के पक्ष में और रखैल के खिलाफ भी मानता है जब एक पुरुष और महिला लंबे समय तक लगातार सहवास करते हैं। यहाँ यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कोई पुरुष अपने द्विविवाह की याचिका दायर करता है, तो न्यायालय उसकी पिछली शादी के सख्त सबूत पर जोर देगा। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "1. कानून के तहत, एक दूसरी पत्नी जिसकी शादी एक जीवित पत्नी के साथ अपने पति की पिछली शादी के जीवित रहने के कारण अमान्य है, वह कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है और इसलिए, वह केवल इस कारण से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है कि "कानून वैधता के पक्ष में झुकता है और कमीने पर गुस्सा करता है [मोहब्बत अली खान बनाम मोहम्मद। इब्राहिम खान, (1928-29) 56 आईए 201:ए. आई. आर. 1929 पी. सी. 135] "। लेकिन, कानून विवाह के पक्ष में और रखैल के खिलाफ भी मानता है जब एक पुरुष और महिला ने लंबे समय तक लगातार सहवास किया है और जब पुरुष और महिला पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए साबित होते हैं, तो कानून यह मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो जाता है, कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे, न कि रखैल की स्थिति में।
>
> 2. कई न्यायिक घोषणाएँ जो इस चरण तक प्रिवी काउंसिल ने उस धारणा के दायरे पर विचार किया है जिसे एक साथ रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच विवाह के संबंध के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन, जब पति द्वारा उपेक्षित पत्नी के इस दावे को नकारने का प्रयास किया जाता है कि वह पहले से ही विवाहित थी, तो अदालत पहले की शादी के सख्त सबूत पर जोर देगी और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को निराश्रितों के रूप में रहने से बचाना है और यह स्पष्ट रूप से भरण-पोषण प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को शामिल करने का भी उद्देश्य है। "
>
> (जोर दिया गया)

39. पिला मुत्यालम्मा मामले (उपरोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में, उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय को धारा 125 Cr.PC के तहत किसी कार्यवाही में विवाह और बच्चे के माता-पिता के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

> "15. अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय को भरण पोषण प्रदान करने वाले आदेश में दर्ज साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है; अधिक से अधिक यह अधिकार क्षेत्र की पेटेंट त्रुटियां को ठीक कर सकता है। सुरेश मंडल बनाम झारखंड राज्य [(2006) 1 ए. आई. आर. झार आर. 153] सहित निर्णयों की एक श्रृंखला में यह निर्धारित किया गया है कि एक ऐसे मामले में जहां विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह मानते हुए भरण-पोषण प्रदान किया है कि पत्नी की उपेक्षा की गई थी और पत्नी भरण-पोषण की हकदार थी, पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। पुनरीक्षण न्यायालय अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं करेगा और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज भरण पोषण आदेश को बाधित नहीं करेगा।
>
> 16. धारा 125 सी. आर. पी. सी. के तहत कार्यवाही में पारित भरण पोषण आदेश के खिलाफ एक संशोधन में, पुनरीक्षण न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत, यह प्रश्न कि क्या आवेदक एक विवाहित पत्नी है, बच्चे वैध/अवैध हैं, तथ्य के प्रमुख प्रश्न होने के कारण, फिर से नहीं खोले जा सकते हैं और पुनरीक्षण न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है कि अपने विचारों को प्रतिस्थापित करें। इसलिए, उच्च न्यायालय को संशोधन में विवाह और बच्चे के संरक्षण के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां निष्कर्ष नकारात्मक है, उच्च न्यायालय संशोधन पर विचार करेगा, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त निष्कर्ष या निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ हैं या नकारात्मक निष्कर्ष के रूप में बच्चे और महिला दोनों के जीवन पर बुरे परिणाम डालते हैं। संतोष बनाम नरेश पाल [(1998) 8 एस. सी.

सी. 447] और पार्वती रानी साहू बनाम बिष्णुपद साहू [(2002) 10 एस. सी. सी. 510 में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया थाः2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1140]इस प्रकार, धारा 125 सी. आर. पी. सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत भरण पोषण का निर्धारण करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की प्रभावकारिता और मूल्य पर अधिकारियों के एक समूह से जो अनुपात निकलता है, वह यह है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। " (जोर दिया गया)

40. कमला बनाम एम. आर. मोहन कुमार, (2019) 11 एस. सी. सी. 491 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध निर्णय दिया है कि विवाह की धारणा है जहां एक पुरुष और एक महिला काफी समय तक पति और पत्नी के रूप में रहते हैं, जो महिला और उनसे पैदा हुए बच्चों के लिए भरण-पोषण का हकदार है, जो निम्नानुसार हैः

"15. वैवाहिक कार्यवाही के विपरीत जहां विवाह का सख्त प्रमाण आवश्यक है, धारा 125 सी. आर. पी. सी. (दंड प्रक्रिया संहिता) के तहत कार्यवाही में, सबूत के इस तरह के सख्त मानक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में सारांश है जो व्यभिचार को रोकने के लिए है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब पक्षकार पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, तो यह धारणा है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के दावे के लिए कानूनी रूप से विवाहित जोड़े हैं। सुलझे हुए सिद्धांतों को लागू करते हुए, हाथ में मामले में, अपीलार्थी 1 और उत्तरवादी पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और उनके दो बच्चे भी हुए थे। अपीलार्थी 1 प्रत्यर्थी की पत्नी होने के नाते, वह और बच्चे, अपीलार्थी 2 और 3 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के हकदार होंगे।

16. यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून विवाह के पक्ष में और रखैल के खिलाफ मानता है जब एक पुरुष और महिला ने कई वर्षों के लिए लगातार सहवास किया है।

(जोर दिया गया)

41. धारा 125 दं. प्र. सं. के वैधानिक प्रावधानों और ऊपर चर्चा किए गए न्यायिक उदाहरणों से, कानूनी रूप से विवाहित पत्नी अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने

की हकदार है, भले ही वह पर्याप्त कारण से अलग रह रही हो और उसके पास पर्याप्त साधन होने के बावजूद, अपनी पत्नी की उपेक्षा करने या उसे बनाए रखने से इनकार करने के बावजूद खुद को और पति को बनाए रखने का कोई साधन नहीं है।

42. यह भी सामने आता है कि वैवाहिक कार्यवाही के विपरीत, जहां धारा 125 दं.प्र.सं के तहत कार्यवाही में विवाह का सख्त सबूत आवश्यक है, सबूत का ऐसा सख्त मानक आवश्यक नहीं है क्योंकि यह संक्षिप्त प्रकृति का है और इसका उद्देश्य पत्नी की अनैतिकता और अभाव को रोकना है और परित्यक्त/उपेक्षित पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय की आपूर्ति में त्वरित उपाय प्रदान करना है। **कमला केस** (ऊपर) का संदर्भ लें

43. यह भी सामने आता है कि यदि पुरुष अपने या याचिकाकर्ता/पत्नी के द्विविवाह के कारण याचिकाकर्ता/पत्नी के साथ अपनी शादी की अयोग्यता का अनुरोध करता है, तो उसे अपने या याचिकाकर्ता/पत्नी के पिछले विवाह के अपने आरोप को सख्त सबूत के साथ साबित करने की आवश्यकता होती है। **विमला (के) मामले** (ऊपर) का संदर्भ लें।

44. यह भी सामने आता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान किसी अन्य महिला से उससे अपनी छिपाकर पुनर्विवाह करता है। पहली जीवित शादी में, उसे द्विविवाह की अपनी गलत याचिका का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी भरण-पोषण की हकदार होती है। **बादशाह केस** (ऊपर) का संदर्भ लें।

45. यह भी सामने आता है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में, उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और विवाह या बच्चे के पितृत्व की वैधता के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि अधिकार क्षेत्र या कानून के तथ्य या त्रुटियां के निष्कर्ष की पेटेंट विकृति न हो। **प्रवती रानी साहु मामले** का संदर्भ लें (ऊपर)।

46. धारा 125 भा.दं.सं के वैधानिक प्रावधानों से यह भी स्पष्ट होता है कि नाबालिग बेटी, चाहे वैध हो या अवैध, विवाहित हो या अविवाहित, अपने पिता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है, यदि वह अपनी शादी तक अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। नाबालिग बेटी का ऐसा भरण-पोषण हिंदू भरण पोषण और गोद लेने के अधिनियम की धारा 20 के तहत भी प्रदान किया जाता है, जो इस प्रकार हैः

> "20. बच्चों और वृद्ध माता-पिता का भरण पोषण (1)इस धारा के प्रावधानों के अधीन, एक हिंदू अपने जीवनकाल के दौरान, अपने वैध या अवैध बच्चों और अपने वृद्ध या दुर्बल माता-पिता को बनाए रखने (भरणपोषण) के लिए बाध्य है।
>
> (2) एक वैध या अवैध बच्चा अपने पिता या माँ से भरण-पोषण का दावा कर सकता है जब तक कि बच्चा नाबालिग है।
>
> (3) अपने वृद्ध या अशक्त माता-पिता या अविवाहित बेटी को बनाए रखने (भरणपोषण) का दायित्व माता-पिता या अविवाहित बेटी तक फैला हुआ है, जैसा कि मामले में है। अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से खुद को बनाए रखने में (भरणपोषण) असमर्थ हो सकता है।
>
> स्पष्टीकरण-—इस खंड में "माता-पिता"में एक निःसंतान सौतेली माँ शामिल है।
>
> (जोर दिया गया)

47. जगदीश जुग्तावत बनाम मंजू लता, (2002) 5 एस. सी. सी. 422 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "4. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि हिंदू गोद लेने और भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 (3) में नाबालिग लड़की के विवाह तक वयस्क होने के बाद माता-पिता से भरण-पोषण के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसलिए, परिवार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बनाए रखने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 125 सीआरपीसी और धारा 20 (3) के संयुक्त पठन पर आधारित है। उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय/आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। "

(जोर दिया गया)

48. सुभाष राय चौधरी बनाम बिहार राज्य, 2003 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 1083 में, इस **न्यायालय** ने हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 क धारा 125 Cr.PC और धारा 20 में निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया है।

> "7. इस प्रकार अधिनियम की धारा 125 (1) (बी) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि पहली में एक बड़ी अविवाहित बेटी को भरण-पोषण का प्रावधान नहीं है, जबकि बाद में ऐसा किया जाता है। इस प्रकार दो कानून हैं जो भरण पोषण के अनुदान के लिए प्रावधान करते हैं। मेरी राय में जब दो कानून संबद्ध विषयों से संबंधित हैं तो दोनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि ऐसा नियम लागू किया जाता है तो यह एक ही विषय से संबंधित विभिन्न कानूनों के बीच किसी भी स्पष्ट विरोधाभास से बच जाएगा। यह अभिनिर्धारित करना कानून का उचित निर्माण नहीं होगा कि संहिता के तहत एक बड़ी अविवाहित बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी, लेकिन उसी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला अधिनियम, से अविवाहित बेटी भरण-पोषण की हकदार होगी। जब मैं निर्माण के उक्त नियम को लागू करता हूं तो यह स्पष्ट होता है कि बालिग होने के बाद माता-पिता से भरण-पोषण के लिए बड़ी अविवाहित लड़की का अधिकार संहिता की धारा 125 और अधिनियम की धारा 20 (3) के संयुक्त पठन से प्रवाहित होता है।

(जोर दिया गया)

49. अभिलाषा बनाम प्रकाश, **(2021) 13** एस. सी. सी. **99** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा **20** का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "12. 1956 के अधिनियम को हिंदुओं के बीच गोद लेने और भरण पोषण से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (1) के साथ-साथ 1956 के अधिनियम की धारा 20 का एक समग्र अवलोकन इंगित करता है कि जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 बच्चे के भरण-पोषण के दावे को तब तक सीमित करती है जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। धारा 125 (1) (सी) के आधार पर, एक अविवाहित बेटी भले ही वयस्क हो गई हो, भरण-पोषण की हकदार है, जहां ऐसी अविवाहित बेटी किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता

या चोट के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। इस प्रकार, सी. आर. पी. सी. की धारा 125 (1) के तहत योजना में विचार किया गया है कि एक बेटी द्वारा भरण-पोषण का दावा, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, केवल तभी स्वीकार्य है जब वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद को बनाए रखने (भरणपोषण) में असमर्थ हो। वर्तमान मामले में, पुनरीक्षण न्यायालय ने एक निष्कर्ष वापस किया है कि अपीलार्थी किसी भी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट से पीड़ित नहीं है जिसके कारण वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। उपरोक्त निष्कर्षों पर हमारे सामने सवाल भी नहीं उठाए गए हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भले ही वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट से पीड़ित न हो, 1956 के अधिनियम की धारा 20 के आधार पर, वह तब तक भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है जब तक कि वह अविवाहित न हो।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामला

इस न्यायालय के साक्ष्य और निष्कर्षों की सराहना

50. अभिलेख पर साक्ष्य के अवलोकन से मुझे पता चलता है कि परिवार न्यायालय के समक्ष आवेदक रेणु कुमारी के मामले में। *प्रथम दृष्टया* साबित हुआ कि नथुनी पासवान ने गुलाबी देवी के साथ अपनी पिछली शादी को छिपाते हुए हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार 25.06.2002 पर देवघर के शिव मंदिर में उससे शादी की थी। इसलिए, वह गुलाबी देवी के साथ अपनी पिछली शादी की दलील यह दिखाने के लिए नहीं ले सकता कि रेणु कुमारी के साथ उसकी शादी कानूनी रूप से वैध नहीं है। बादशाह मामले (ऊपर) का संदर्भ लें।

51. यह भी प्रथम दृष्टया साबित होता है कि शादी के बाद, रेणु कुमारी खगड़िया में अपने सरकारी क्वार्टर में नथुनी पासवान के वैवाहिक घर में शामिल हो गईं और उनकी

शादी से पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी का जन्म दिनांक- 09.02.2012 को हुआ था और वह अभी भी अपनी नाबालिग बेटी पीहू कुमारी के साथ क्वार्टर में रह रही हैं।

52. नथुनी पासवान के साथ अपनी शादी के बारे में रेणु कुमारी की दलील का समर्थन न केवल उनके अपने बयान से किया गया है, बल्कि मुकदमे के दौरान उनके गवाहों द्वारा भी इसकी जांच की गई है। वह दस्तावेजी प्रमाण या शादी की तस्वीरें प्रस्तुत नहीं कर सकीं क्योंकि वे नथुनी पासवान के पास थीं। यह भी खारिज कर दिया गया है कि बेटी पीहू कुमारी के नाम पर स्कूल रजिस्टर और एल. आई. सी. की पॉलिसी में भी उसके पिता के रूप में नथुनी पासवान का नाम है। सुनवाई के दौरान जब उनका सामना रेणु कुमारी के साथ किया गया, तो नथुनी पासवान की एक संयुक्त तस्वीर प्रस्तुत की गई है उन्होंने इसे सच माना।

53. मुझे आगे पता चलता है कि नथुनी पासवान ने दावा किया है कि उनके साथ रेणु कुमारी की कथित शादी से पहले ही रेणु कुमारी की शादी धीरज सिंह से हो चुकी थी। हालांकि, कानून के अनुसार, नथुनी पासवान को धीरज सिंह के साथ रेणु कुमारी की पिछली शादी को सख्त सबूतों से साबित करना आवश्यक है। लेकिन मुझे लगता है कि वह अपने दावे के समर्थन में ऐसे सबूत पेश करने में विफल रहे हैं। कानून के अनुसार, उन्हें कार्यवाही में धीरज सिंह को शामिल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह आवश्यक पक्षकार थे और कार्यवाही में उनकी उपस्थिति के बिना, रेणु कुमारी के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति घोषित नहीं की जा सकती थी।

54. इस संबंध में डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैयाम्मल का उल्लेख किया जा सकता है। (2010) 10 एस. सी. सी. 469, जिसे इस रूप में माना जाता है:

> "9. हमारी राय में, चूंकि लक्ष्मी को परिवार न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था और उसे कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए अपीलार्थी के साथ उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई भी घोषणा पूरी तरह से अमान्य है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के

> नियमों का उल्लंघन होगा। लक्ष्मी को सुनवाई किए बिना निचली अदालतों द्वारा ऐसी कोई घोषणा वैध रूप से नहीं दी जा सकती थी कि उसने इसमें अपीलार्थी से शादी नहीं की थी क्योंकि इस तरह का निष्कर्ष उसके अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। और यदि ऐसी कोई घोषणा नहीं दी जा सकती थी तो स्पष्ट रूप से कोई घोषणा वैध रूप से नहीं दी जा सकती थी कि अपीलार्थी वैध रूप से उत्तरवादी से विवाहित था, क्योंकि यदि लक्ष्मी अपीलार्थी की पत्नी थी तो उसे तलाक दिए बिना अपीलार्थी वैध रूप से उत्तरवादी से शादी नहीं कर सकता था।
>
> (जोर दिया गया)

55. मुझे यह भी पता चलता है कि कोई दस्तावेजी सबूत और न मुकदमे के दौरान उसने धीरज सिंह के साथ रेणु कुमारी की कथित शादी का चश्मदीद गवाह पेश किया है। इसलिए, मुझे लगता है कि नथुनी पासवान यह साबित करने में विफल रहे हैं कि रेणु कुमारी की पहले धीरज कुमार के साथ शादी हुई थी।

56. इसलिए, मुझे, *प्रथम दृष्टया,* पता चलता है कि रेणु कुमारी कानूनी रूप से नथुनी पासवान की विवाहित पत्नी है और पीहू कुमारी उर्फ रुचि कुमारी उनकी शादी से पैदा हुई है और पीहू कुमार नाबालिग है। इसलिए, कानून के अनुसार, रेणु कुमारी और पीहू कुमारी दोनों नथुनी पासवान से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं।

57. मुझे यह भी पता चला है कि नथुनी पासवान की मासिक आय रु। उनके वेतन से 70,000/- रुपये और रेणु कुमारी और पीहू कुमारी के पास अपना भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं है, हालांकि वे नथुनी के नाम पर आवंटित सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं और नथुनी के वेतन से किराया काटा जा रहा है।

58. मैं यह भी पाता हूँ कि रेणु कुमारी और पीहू कुमारी के अलावा, नथुनी पासवान की एक और कानूनी रूप से विवाहित पत्नी गुलाबी देवी भी नथुनी पासवान पर

आश्रित हैं। इसलिए, रेणु कुमारी और पीहू कुमारी के पक्ष में विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा के संबंध में, मैं पाता हूँ कि नथुनी पासवान के आश्रितों की संख्या के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि रेणु कुमारी और पीहू कुमारी नथुनी पासवान के नाम पर आवंटित सरकारी क्वार्टर में रह रही हैं और क्वार्टर का किराया उनके वेतन से काटा जा रहा है, दिया गया भरण-पोषण अधिक है।

59. अतः भरण-पोषण याचिका दाखिल करने की तिथि अर्थात 03.07.2014 से रेणु कुमारी को 5,000/- रूपये तथा पीहू कुमारी को उसके विवाह तक 3,000/- रूपये का मासिक भुगतान किया जाना न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगा।

60. तदनुसार, वर्तमान याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 32 एम/2014 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.08.2019 को संशोधित किया जाता है याचिकाकर्ता/नथुनी पासवान को दिनांक 03.07.2014 की तिथि से रेणु कुमारी तथा पीहू कुमारी को क्रमशः 5,000/- रूपये तथा 3,000/- रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

61. हालांकि, मामले से अलग होने से पहले, यह स्पष्ट करना उचित होगा कि रेणु कुमारी और नथुनी पासवान के बीच विवाह की वैधता और पीहू कुमारी के पितृत्व के बारे में इस न्यायालय का निष्कर्ष धारा 125 सीआरपीसी के तहत इस कार्यवाही में अस्थायी प्रकृति का है। नथुनी पासवान रेणु कुमारी की वैवाहिक स्थिति और पीहू कुमारी के पितृत्व की अंतिम घोषणा के लिए सिविल न्यायालय/पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उचित वैवाहिक याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

62. निचली अदालत का रिकॉर्ड तुरंत निचली अदालत को वापस भेजा जाए।

63. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

64. विद्वान रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय/आदेश की एक प्रति बिहार के सभी पारिवारिक न्यायालयों में प्रसारित करें तथा इसकी एक प्रति बिहार न्यायिक अकादमी को भी भेजें, ताकि पारिवारिक न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस पर चर्चा की जा सके।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

शोएब/
रविशंकर/
चंदन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।